UPSMA
UP SUGAR MILLS ASSOCIATION

वार्ता
The Dialogue

MARCH, 2025 — Monthly Newsletter of UPSMA — VOL: III, ISSUE: 306

NEWSMAKERS

भारत से 5 लाख टन चीनी निर्यात के सौदे, मिलों को 44 हजार रुपये/टन तक मिल रही कीमतें

चीनी उद्योग सूत्रों के मुताबिक, निर्यात के लिए चीनी के सौदे 44 हजार रुपये प्रति टन तक हो रहे हैं। अधिकांश निर्यात महाराष्ट्र की चीनी मिलों से हो रहा है। अफ्रीकी देशों, अफगानिस्तान और श्रीलंका समेत करीब दर्जन भर देशों को चीनी बेची जा रही है। अब तक 2 लाख चीनी का निर्यात हो चुका है और 3 लाख टन निर्यात सौदे हो चुके हैं।

केंद्र सरकार द्वारा चालू पेराई सीजन (2024-25) के दौरान 10 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति देने के करीब एक महीने के भीतर 5 लाख टन चीनी के निर्यात सौदे हो चुके है। इसमें से 2 लाख चीनी का निर्यात हो चुका है। चीनी निर्यात का फैसला मिलों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। निर्यात के लिए चीनी की एक्स-फैक्ट्री कीमत 44000 रुपये प्रति टन तक पहुंच गई है।

चीनी उद्योग सूत्रों के मुताबिक, निर्यात के लिए चीनी के सौदे 44 हजार रुपये प्रति टन तक हो रहे हैं। अधिकांश निर्यात महाराष्ट्र की मिलों से हो रहा है। अफ्रीकी देशों, अफगानिस्तान और श्रीलंका समेत करीब दर्जन भर देशों को चीनी भेजी जा रही है। अब तक 2 लाख चीनी का निर्यात हो चुका है और 3 लाख टन निर्यात के सौदे हो चुके हैं। चीनी मिलों द्वारा निर्यात के लिए चीनी की कीमत को लेकर काफी मोलभाव किया जा रहा है। इसी वजह से कीमत 44 हजार रुपये प्रति टन तक पहुंच गई है। ऐसे में महाराष्ट्र की कई चीनी मिलों द्वारा चालू पेराई सीजन में किसानों को गन्ने के लिए फेयर एंड रिम्यूनेरेटिव प्राइस (एफआरपी) से अधिक कीमत का भुगतान किये जाने की संभावना बन रही है।

चीनी की कीमतें बढ़ी

चालू सीजन में चीनी के उत्पादन में गिरावट के चलते कीमतों में तेजी आई है। घरेलू बाजार में भी चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र में चीनी की एक्स फैक्टरी कीमत 3800 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास चल रही है जबकि उत्तर प्रदेश में चीनी की एक्स फैक्टरी कीमत 4000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास है। हालांकि, सरकार ने चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) 3100 रुपये प्रति क्विंटल तय कर रखा है जबकि चीनी मिलें इसे बढ़ाकर 3900 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग कर रही हैं।

उत्पादन में गिरावट

चालू सीजन 2024-25 में चीनी उद्योग ने 270 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया है जो पिछले साल के मुकाबले करीब 50 लाख टन कम है। पिछले सीजन (2023-24) में 319 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। चीनी के बड़े उत्पादक राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने कि कमजोर फसल के चलते उत्पादन कम रहा है। उद्योग सूत्रों ने आशंका जताई है कि चीनी उत्पादन 270 लाख टन से भी नीचे जा सकता है।

सरकार ने चालू पेराई सीजन में गन्ना जूस और बी-हैवी मोलेसेज के जरिये 37.5 लाख टन चीनी का डायवर्जन एथेनॉल उत्पादन के लिए करने की अनुमति दी है। लेकिन सरकार ने इन दोनों श्रेणियों के लिए एथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की है। ऐसे में चीनी की बेहतर कीमतों को देखते हुए चीनी मिलें एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी का कम उपयोग कर सकती हैं। उस स्थिति में चीनी का कुल उत्पादन बढ़ सकता है।

Continued on the next page ...

Office: 403 - Chintels House, 16-Station Road, Lucknow-226001 | Phone: +91-522-2635127, 2636482 | E-mail: upsma@upsma.org | Visit us at: www.upsma.org

UPSMA
UP SUGAR MILLS ASSOCIATION

वार्ता
The Dialogue

MARCH, 2025 — Monthly Newsletter of UPSMA — VOL: III, ISSUE: 306

निर्यात की संभावनाएं

उद्योग सूत्रों का कहना है कि हमारे पास 10 लाख टन निर्यात करने के लिए सितंबर, 2025 तक का समय है। इस साल बेहतर कीमत मिलने के चलते अगले साल अधिक निर्यात की संभावना है और यह 40 से 50 लाख टन तक पहुंच सकता है क्योंकि अगले दो साल गन्ने का अधिक उत्पादन होने का अनुमान है।

भारत ने सर्वाधिक 112 लाख टन चीनी का निर्यात वर्ष 2021-22 में किया था और उसी साल देश में रिकॉर्ड 360 लाख टन चीनी उत्पादन हुआ था। साल 2022-23 में 63 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया था। सरकार ने अक्तूबर, 2023 में चीनी निर्यात को रेस्ट्रिक्टेट लिस्ट में डाल दिया था और 2023-24 में चीनी निर्यात कोटा जारी नहीं किया था। इस साल सरकार ने 20 जनवरी को चीनी निर्यात पर प्रतिबंध हटाते हुए चालू सीजन में 10 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी।

Source: Rural voice, 26th February, 2025

भारत पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिश्रण को 20 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य बना रहा है: मंत्री हरदीप सिंह पुरी

नई दिल्ली : भारत पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को 20 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य बना रहा है, और इस पर विचार करने के लिए नीति आयोग के तहत एक समिति का गठन किया है, 26 फरवरी, 2025 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा। 'एडवांटेज असम 2.0' बिजनेस समिट में बोलते हुए, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 19.6 प्रतिशत की मिश्रण दर पहले ही हासिल की जा चुकी है।

उन्होंने कहा, हम जैव ईंधन के 20 प्रतिशत से अधिक मिश्रण का लक्ष्य बना रहे हैं। इस पर विचार करने के लिए नीति आयोग का एक समूह पहले ही गठित किया जा चुका है। पुरी ने इस बात पर भी जोर दिया कि, भारत की सभी जीवाश्म ईंधन कंपनियां देश की विकासात्मक चुनौतियों के बावजूद 2045 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

चालू एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2024-25 में, जनवरी में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण 19.6 प्रतिशत तक पहुँच गया, और नवंबर 2024 से जनवरी 2025 तक संचयी औसत एथेनॉल मिश्रण 17.4 प्रतिशत तक पहुँच गया। जनवरी 2025 में प्राप्त एथेनॉल मिश्रण प्रतिशत अब तक का सबसे अधिक है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को जनवरी 2025 में ईबीपी कार्यक्रम के तहत 91.7 करोड़ लीटर एथेनॉल प्राप्त हुआ, जिससे नवंबर 2024 से जनवरी 2024 तक संचयी कुल 200.8 करोड़ लीटर हो गया। उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2025 में ईबीपी कार्यक्रम के तहत मिश्रित एथेनॉल की मात्रा 82.1 करोड़ लीटर थी, जो नवंबर 2024 से जनवरी 2025 तक कुल 222.9 करोड़ लीटर थी ।

Source: Chinimandi, 26th February, 2025

सरकार ने मार्च 2025 में घरेलू बिक्री के लिए 23 लाख मीट्रिक टन मासिक चीनी कोटा तय किया

नई दिल्ली : खाद्य मंत्रालय ने 25 फरवरी को एक घोषणा में मार्च 2025 के लिए 23 लाख मीट्रिक टन (LMT) का मासिक चीनी कोटा आवंटित किया, जो मार्च 2024 में आवंटित कोटा से कम है। मार्च 2024 में, सरकार ने घरेलू बिक्री के लिए 23.5 लाख मीट्रिक टन का मासिक चीनी कोटा आवंटित किया था।

फरवरी 2025 के लिए, सरकार ने 22.5 लाख मीट्रिक टन चीनी कोटा आवंटित किया था।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, गर्मी और त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही घरेलू बाजार में सकारात्मक माहौल बना रहेगा। चीनी मिलों के पेराई सत्र के खत्म होने से भी बाजार को समर्थन मिलेगा।

Source: Chinimandi, 25th February, 2025

उत्तराखंड में भी इस साल नहीं बढ़ेगा गन्ने का मूल्य

देहरादून : उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी इस साल गन्ने का मूल्य नहीं बढाने का फैसला किया है। धामी कैबिनेट ने पिछले साल के मूल्य को इस बार भी यथावत रखने का निर्णय लिया है। जिसके तहत अगेती का 375 और सामान्य प्रजाति का 365 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य मिलेगा। कैबिनेट में आए प्रस्ताव में कहा गया कि राज्य की सहकारी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों की ओर से पेराई सत्रों के दौरान क्रय किए जाने वाले गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य इसके लिए गठित राज्य परामर्शी समिति की संस्तुति के आधार पर तय किया जाता है।

राज्य परामर्शी समिति की संस्तुति के आधार पर पिछले पेराई सत्र के लिए तय गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य को चालू पेराई सत्र 2024-25 में यथावत रखे जाने का निर्णय

Continued on the next page ...

Office: 403 - Chintels House, 16-Station Road, Lucknow-226001 | Phone: +91-522-2635127, 2636482 | E-mail: upsma@upsma.org | Visit us at: www.upsma.org

UPSMA
UP SUGAR MILLS ASSOCIATION

वार्ता
The Dialogue

MARCH, 2025 — Monthly Newsletter of UPSMA — VOL: III, ISSUE: 306

लिया गया है। वहीं, पिछले पेराई सत्र की तरह गन्ना विकास अंशदान (कमीशन) की दर 5.50 रुपए प्रति क्विंटल तय किए जाने की भी मंजूरी दी गई। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों किसानों में नाराजगी का माहोल बना हुआ है। किसानों के अनुसार, फसल लागत बढ़ने के कारन गन्ना मूल्य बढ़ाने की जरूरत थी।

Source: chinimandi.com, 4th March, 2025

चीनी उत्पादन के अनुमानों पर संशय, दाम बढ़े तो आ सकती है आयात की नौबत

ऐसे समय जब देश में चीनी उत्पादन में गिरावट है तब सरकार ने 10 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी है। लेकिन जिस तरह से घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं उससे त्योहारी सीजन में चीनी आयात की नौबत आ सकती है।

चीनी उद्योग की जबरदस्त लॉबिंग के चलते केंद्र सरकार ने चालू सीजन (2024-25) में 10 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी। लेकिन जिस तरह से चीनी उत्पादन में गिरावट के आंकड़े आ रहे हैं, उसके चलते इस निर्णय पर सवाल उठ सकते हैं । निर्यात में तेजी और उत्पादन में गिरावट के चलते घरेलू बाजार में चीनी की एक्स फैक्टरी कीमतें 4100 रुपये प्रति क्विंटल को पार कर गई हैं। वहीं रिटेल कीमतें 45 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई हैं। ऐसे में अब लगातार चीनी उत्पादन और इसकी कीमतों की समीक्षा हो रही है। अगर उत्पादन में गिरावट बढ़ती है तो चीनी की कीमतों में तेजी आएगी। साथ ही सीजन के अंत में बकाया स्टॉक घटकर 50 लाख टन से नीचे रह सकता है उस स्थिति में देश में चीनी के आयात की स्थिति पैदा हो सकती है।

चीनी उत्पादन में कमी की मुख्य वजह उत्तर प्रदेश में रोगों के चलते गन्ना उत्पादन में गिरावट आना है। वहीं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और अन्य राज्यों में गन्ने से चीनी की रिकवरी में भी एक फीसदी तक की गिरावट आई है। गन्ने की कमी के चलते देश की करीब एक तिहाई (186) चीनी मिलें फरवरी में ही बंद हो चुकी हैं।

उद्योग सूत्रों का कहना है कि चीनी उत्पादन के ताजा अनुमान चिंताजनक हैं और अब देश में चीनी उत्पादन 260 से 265 लाख टन के आसपास रहने की संभावना है जो पिछले साल के 319 लाख टन चीनी उत्पादन के मुकाबले 55 से 60 लाख टन कम रहेगा। देश की घरेलू चीनी खपत लगभग 285 लाख टन सालाना है। यानी उत्पादन खपत से करीब 25 लाख टन तक कम रह सकता है। पिछले सीजन के अंत में देश में चीनी का करीब 80 लाख टन का बकाया स्टॉक था। 10 लाख टन निर्यात होने और उत्पादन में गिरावट के चलते चालू चीनी सीजन के अंत में स्टॉक 50 लाख टन से नीचे आ सकता है।

उद्योग जगत के कुछ जानकर तो इस सीजन के आखिर में चीनी स्टॉक 40 लाख टन के आसपास रहने की आशंका जता रहे हैं। तय मानकों के मुताबिक तीन माह की खपत के बराबर स्टॉक होना चाहिए जो करीब 70 लाख टन बैठता है। उत्पादन में कमी का अहसास होने के चलते मार्च के लिए खुले बाजार में चीनी की कोटा भी पिछले साल से कम जारी किया गया है।

वहीं, चीनी की बेहतर कीमतों के चलते अधिकांश चीनी मिलों ने गन्ने के जूस से सीधे एथेनॉल उत्पादन को बंद कर दिया है। साथ ही बी-हैवी मोलेसेज से एथेनॉल उत्पादन को भी अधिकांश चीनी मिलों ने बहुत कम कर दिया है। इसके पीछे चीनी मिलें इन दोनों श्रेणियों के एथेनॉल की कीमतों को सरकार द्वारा नहीं बढ़ाने को वजह बता रही हैं।

Source: Ruralvoice, 4th March, 2025

आधी खूड़ सिचाई विधि अपनाएं किसान 60 प्रतिशत तक पानी की बचत होगी

गन्ने की फसल में धान की तरह अधिक पानी की जरूरत होती है। आमतौर पर 100 टन प्रति हेक्टेयर उपज के लिए 1000 मिलीमीटर पानी की आवश्यक्ता पड़ती है। यह 1200 मिलीमीटर तक भी हो सकता है। फिलहाल गन्ने की बिजाई का समय 15 मार्च तक ही बचा है। एचएयू रीजनल रिसर्च स्टेशन करनाल के प्रधान मृदा वैज्ञानिक (सेवानिवृत्त) डॉ ० विजय कुमार अरोड़ा ने बताया कि गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नत सिंचाई विधियां अपनाकर पानी की बचत की जा सकती है। अप्रैल, मई, जून में क्यारी में बोई जाने वाली फसल और खूडो में सिंचाई करने से पानी कम लगता है। इसी प्रकार ट्रैंच में बोए गए गन्ने को साधारण विधि की तुलना में पानी कम लगता है, जबकि चिकनी मिटटी व दोमट मिटटी की अपेक्षा रेतीली मिटटी में पानी की जरूरत अधिक होती है। पहली सिंचाई गन्ने की बुवाई के 5 -6 सप्ताह बाद और अगली सिंचाइयाँ 10 दिन के अंतराल पर मानसून के आने से पहले और मानसून के बाद 25 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करे आमतौर पर गन्ने में 8 सेंटीमीटर की 12 बार सिंचाई की जाती है। गेंहूं की कटाई के बाद गन्ने की बिजाई के लिए आधा खूड़ विधि उत्तम है, क्योंकि खेत की तैयारी सूखे में करने की वजह से 7 से 10 दिन पहले बिजाई कर सकते है। ज्यादा गर्मी में भी पोरियों के आस - पास नमी बनी रहती है। इसमें जमाव के समय नमी रहने की वजह से दीमक के प्रकोप की सभावना भी काम हो जाती है। हरियाणा में किसान सिंचाई खुले पानी से करते है ऐसा करने से जहां पानी ज्यादा व्यर्थ होता है

Source: Dainikbhaskar, 6th March, 2025

P.T.O...

Office: 403 - Chintels House, 16-Station Road, Lucknow-226001 | Phone: +91-522-2635127, 2636482 | E-mail: upsma@upsma.org | Visit us at: www.upsma.org

UPSMA
UP SUGAR MILLS ASSOCIATION

वार्ता
The Dialogue

MARCH, 2025 — Monthly Newsletter of UPSMA — VOL: III, ISSUE: 306

ETHANOL BOOST: E100 FUEL NOW AVAILABLE AT 400 PLUS OUTLETS NATIONWIDE

India is firmly positioned as the third-largest biofuel producer globally, leading the transition to cleaner and renewable energy, said Hardeep Singh Puri, the Minister of Petroleum and Natural Gas, on Monday.

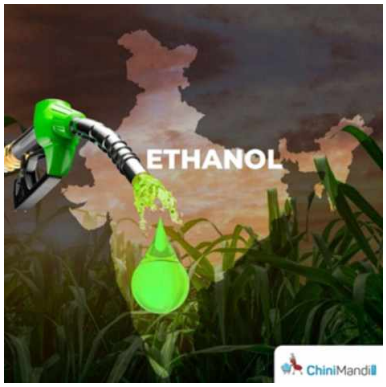

In a post on the social media platform X, the minister emphasized that "India has achieved 19.6% ethanol blending in petrol as of January this year and is on track to reach 20% soon—five years ahead of the original 2030 target—reducing fuel imports and emissions."

Over the past decade, ethanol blending initiatives have boosted farmers' incomes, as ethanol is derived from sugarcane, created rural employment, cut CO2 emissions, and saved foreign exchange, according to official data.

Public sector oil companies, including Indian Oil, Bharat Petroleum, and Hindustan Petroleum, have led this effort, rolling out various ethanol-petrol blends across the nation.

The minister further noted that "E100 fuel is now available at over 400 outlets nationwide, bringing India closer to a cleaner, greener future. This is a journey of progress, innovation, and sustainability."

Source: Chinimandi, 3rd March, 2025

PIPRAICH SUGAR MILL TO BEGIN ETHANOL PRODUCTION WITH 90CR ALLOCATION

Gorakhpur: Pipraich sugar mill, known for producing sulphur-free sugar, is set to expand its operations with ethanol production. The UP govt has allocation ted Rs 90 crore in the 2025-26 Budget to establish a distillery at the mill, with a production capacity of 60 kilolitres per day. This move will ensure faster payments to sugarcane farmers. Established as a private sugar mill in 1932, Pipraich was acquired in 1974 but shut down in 1999.

Officials said that when chief minister Yogi Adityanath was MP he consistently advocated for the revival of closed sugar mills, but past govt. paid little attention. After becoming CM in 2017, he fulfilled his promise by inaugurating a new sugar mill at the same site, bringing relief to farmers. On Nov 17, 2019, the mill commenced operations in record time, officials said.

Source: Sugar times, 28th February, 2025

Knowledge Box

As early as 1920 a batch of sugarcane seeds derived from the hardiest parents was sent to Saharanpur in the United Provinces. With the hearty cooperation of the officer in charge of the Botanic Gardens there, an attempt was made to germinate the seed at Saharanpur and grow them to maturity in the gardens. The seeds were germinated inside a hot house and, at the end of a year; it was found that the seedlings had not grown sufficiently for selection. The matter was accordingly dropped at the time.

John Firminger Duthie (1845-1922) was the Superintendent of Saharanpur Botanical Gardens from 1875-1903 and he made this garden world famous by his continuous services for about 27 years

In January 1924, a batch of seeds was sent to the Government Station at Anakapalle in the Northern circle of the Madras Presidency to see if the Saharanpur Experiment could be carried out with greater success in a locality with more favourable climatic conditions for the germination of the cane seeds. The experiment was a fair success and, during the year, about 1000 seedlings raised and grown at Anakapalle were studied and fifteen selections made. These selections were watched for their behavior under field conditions.

UPSMA Newsletter titled 'Varta' the Dialogue is providing information on sugar, sugar industry and sugar byproducts. We request you to share your thoughts and experience with us through write-ups, success stories, updates, photographs etc. We publish your creative in the next edition of this newsletter. You are requested to send your entries to be published in UPSMA newsletter through mail at upsma@upsma.org. The newsletter will be uploaded on UPSMA website.

अस्वीकरण: यहाँ दी गई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा या अन्य स्रोतों से ली गई है, जिन्हें विश्वसनीय माना जाता है और इस पर इस तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इस समाचार में दी गई जानकारी में किसी भी अनजाने त्रुटि से किसी भी व्यक्ति को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए 'वार्ता टीम' किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगी। इस दस्तावेज़ में दी गई जानकारी इस समाचार की तारीख तक है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य के परिणाम या घटनाएँ इस जानकारी के अनुरूप होंगी।

Office: 403 - Chintels House, 16-Station Road, Lucknow-226001 | Phone: +91-522-2635127, 2636482 | E-mail: upsma@upsma.org | Visit us at: www.upsma.org